''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (विना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 जनवरी, 2003—माघ 4, शक 1924

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक ४ जनवरी 2003

क्रमांक 27/ 2307/ साप्रवि/ 2002/ 1/ 2/ लीव/ आईएएस.—श्री बी. के. एस. रे, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग को इस विभाग के आदेश क्रमांक 2811/2307/साप्रवि/02/1/आईएएस, दिनांक 22-11-2002 द्वारा दिनांक 13-12-2002 से 18-1-2003 (37 दिन) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था अबंश्री बी. के. एस. रे, के उक्त

अर्जित अवकाश में संशोधन करते हुये श्री रे को दिनांक 16-12-2002 से 23-1-2003 तक (37 दिन) का अर्जित अयकाश स्वीकृत किया जाता है.

इस विभाग के आदेश दिनांक 22-11-2002 में कालम (2)
 से (4) तक यथावत् रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

वित्त तथा योजना विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2002

क्रमांक एफ-8/1/2001/23/आसां.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1/2000/योजना/7, दिनांक 4-12-2000, क्रमांक 24/एफ-8-1/2001/योजना/74, दिनांक 10-1-2001 एवं क्रमांक एफ-8-1/2001/योजना/74, दिनांक 12-2-2002 को अधिक्रमित करते हुए छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 की धारा-4 उपधारा-3 (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम 2 में विनिर्दिष्ट मंत्रि-परिषद् के सदस्यों को सारणी के कालम 3 में विनिर्दिष्ट जिला योजना समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है, जो समिति के अध्यक्ष भी होंगे, अर्थात् :—

ज्ञ मांक	मंत्रि-परिषद् के सदस्यों के नाम	जिला योजना समिति	
(1)	(2)	(3)	
1.	श्री अजीत जोगी, मुख्यमंत्री	रायपुर	•
2.	श्री महेन्द्र कर्मा, मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग	धमत्री	
3.	श्री अमितेष शुक्ल, मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास	महासमुन्द	
4.	श्री रामपुकार सिंह, मंत्री, खनिज साधन एवं जनसंपर्क	रायगढ़	
5.	श्री डेरहू प्रसाद धृतलहरे, मंत्री, वन	जशपुर जशपुर	
6.	श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, मंत्री, सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण.	सरगुजा	
7.	श्री धनेन्द्र साहु, राज्यमंत्री (स्व. प्रभार), पर्यटन संस्कृति	राजनांदगांव	
8.	श्री गंगूराम बघेल, राज्यमंत्री (स्व. प्रभार), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी.	वस्तर	
9.	डॉ. शक्राजीत नायक, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), जल संसाधन.	जांजगीर-चांपा	
10.	श्री मनोज सिंह मंडावी, राज्यमंत्री, निर्माण, पर्यावरण एवं नगरीय विकास, विधि एवं विधायी कार्य, गृह.	बिलासपुर	
11.	श्री विधान मिश्रा, राज्यमंत्री, उद्योग तथा कृषि	कोर बा	. *
12.	श्री बदरुद्दीन कुरैशी, राज्यमंत्री, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास, प्रहिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग.	कवर्धाः -	

(1)	(2)	(3)
13.	श्री ताम्रध्वज साहू, राज्यमंत्री, जल संसाधन, ऊर्जा तथा शिक्षा विभाग.	कांकेर
14.	श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह, राज्यमंत्री, खनिज, जनसंपर्क तथा वित्त विभाग.	दुर्ग
15.	त्री तुलेश्वर सिंह, राज्यमंत्री, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग	दन्तेवाड़ा
16. ·	श्री विक्रम भगत, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, वन तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण.	कोरिया .

·छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. पी. त्रिवेदी, विशेष सचिव.

वन एवं संस्कृति विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2002

क्रमांक एफ 7-68/व. सं./01.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई वन भूमि/बंजर भूमि पर लागू होने की घोषणा इन शर्तों के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर रूपभेदित किये जावें, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जावेंगे.

अनुसूची

वनमण्डल का नाम : रायपुर

जिला : रायपुर

तहसील : रायपुर परिक्षेत्र : रायपुर

क्र.	वनखण्ड का नाम	सम्मिलित ग्राम व प. ह. नं.	राजस्व ग्राम जहां स्थित है	खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1.	खरोरा	खरोरा	. रायपुर	4/1	0.275	उत्तर : कृत्रिम सीमा रेखा
		26		6/2,3	0.672	मुनारा क्र. 1 से 14
				6/1	0.340	तक.
			•	7/1, 2	. 1.352	पूर्व : कृत्रिम सीमा रखा
				8/2	0.421	मुनारा क्र. 14 सं
				13/1	0.890	23 तक.

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. खरोरा	खरोरा	रायपुर	13/3	0.121	दक्षिण : कृत्रिम सीमा रेख
	26	3	14/1, 2, 3	0.379	मुनारा क्र. 23 से
			17, 18, 19, 20	3.605	49 तक.
	•		15, 16	0.583	पश्चिम : कक्ष क्रमांक 8
			12	1.100	सीमा रेखा मु.क्र
			22	1.668	49 से 1 तक
			23	2.833	
•			21/1, 2	1.368	
-		•	81/1	1.918	
1			81/2	1.918	
	•		82, 83, 84, 85	1.994	•
			86	0.429	
			87	0.833	
			88	1.619	
			89/3	0.506	
			89/4	0.510	
			98	0.733	·
			80	0.280	पानी के नीचे
			79/1	0.379	
			79/2	0.194	•
	•		78	0.591	
			77/1, 2	0.591	
			76/1, 2	1.769	
			70	0.551	
			24/1, 2, 3, 4	1.668	
			25/1, 2	1.668	
			26/7, 6	6.021	
			11/3	0.154	
			27/1, 2	2.477	
	•		28/1	1.223	•
			31/5	0.113	
			31/1	0.446	
	•		32/2	0.308	•
			33/1, 2	1.214	
•			30/2	0.663	
	`		99/1, पार्ट	0.051	
		٠	97 पार्ट	0.187	
			31/3, 4	0.890	-
		योग	44	47.505	

) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. नहरडीह	नहरडीह	खरोरा	1/1	0.461	उत्तर : कृत्रिम सीमा रेखा
	25		1/2	0.203	मुनारा, क्र.1से १तव
			1/3	0.202	
	•		1/4	0.320	पूर्व : कृत्रिम सीमा रेखा
			1/5	0.231	मुनारा क्र. ९ से
•			2	0.364	15 तक.
			3	0.324	दक्षिण : कृत्रिम सीमा रेर
		•	4/1, 2	0.158	मुनारा क्र. 15
			4/3, 4	0.158	19 तक.
	-		5/1	0.162	पश्चिम : कृत्रिम सीमा रे
			5/2	0.158	मुनारा क्र. 19
			6/1	0.121	1 तक.
			6/2	0.121	नोट
			6/3.	0.118	(अ) खसरा नं. 61
			7/1	0.663	614,105 को मु
			7/2	0.330	1 से 10 तक रि
			7/3	0.330	आउट किया गय
		-	8	0.247	(ब) खसरा नं. 115/
			9 /1	0.114	को मु.क्र 1से 4 त
		•	9/2	0.344	रिंग आउट किय
			9/3	0.117	गया.
			9/4	0.113	(स) खसरा नं. 14/1
			10	0.567	16/1, 16/3 को
			11	0.275	· क्र. 1 से 7 तक f
			12	.0.235	आउट किया गय
	•		13/1	0.101	
			13/2	, 0.101	
			13/3	0.105	
			13/4	0.162	
			13/5	0.263	
			13/6	0.202	
			19/1	0.394	
			19/2	0.394	
			19/3	0.393	
			21/4	0.599	
•			21/2	. 1.793	
			23/2	0.534	
			24/1	0.598	
			24/2	1.845	
			99/1	0.404	
			99/2	0.814	

)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
2.	नहरडीह	नहरडीह	खरोरा	101/1	0.437	•	
۷.	नहरंडाह	25	Guu	101/1	0.437		
				23/1	1.060		
	•			103/1	0.275		
		,		103/1	0.103		
				103/3	0.307		
				103/4	0.275		
				103/5	0.369		
				104/1	0.595		
	•		•	21/3	0.599		
				21/1	0.599	-	
				106/2	0.676		٠
				107	0.344		
	•			108	0.724		
				109/1	0.375		·
				109/2	0.249		
				109/3	0.375		
		•	•	110	0.567		
		•		111	0.348		
				112	0.405	•	
				113/1	0.194		
		•		113/2	0.194		
		•		114	0.308		
	•			115/1	0.247		
	•		-	13/7	0.267		
				13/8	0.202		
				14/2	0.263		
				14/3	0.522	•	
				15/1	0.425		
				15/2	0.271		
				15/3	0.271	•	
	•			16/2	0.555	•	
				· 17/1	0.457		
				17/2	0.457		
				18/1	0.405		
		•.		18/3	0.809		•
				18/4	0.404		
		•	•	115/3	0.267		
				115/4	0.093		
				115/5	0.267		
		•		115/6	0.243		
				115/7	0.097		

1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
2. नहरडीह	नहरडीह	खरोरा 25	116	2.481		
		योग	85	34.361		. , ,
<u> </u>		कुल योग	129	81.866		·

संक्षिप्त विवरण : यह भूमि पूर्णत: निजी भूमि स्वामी हक की जमीन है. रायपुर जिले की एलॉय एण्ड स्टील लि. से प्रभावित वन भूमि के बदले में वन विभाग को दी गई है.

वनीकरण का : रायपुर एलॉय एण्ड स्टील लि. द्वारा राजनांदगांव में लोह खनिज उत्खनन से प्रभावित वन भूमि की कमी की धितपूर्ति हेतु कारण गैर वन भूमि को वन में शामिल करना है.

Raipur, the 28th December 2002

No. F7-68/F.C./01.—In exercise of the power conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927). The State Government declares the provision of chapter IV of the said act applicable to the forest land/waste land specified in the schedule below subject to the condition that the existing right of individuals or of communities shall not be abridged or effected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District: Raipur

Forest Division: Raipur

Tahsil: Raipur

Range: Raipur

SI. No.	Name of forest block	Name of waste land & P. H. No.	Revenue village where blocks	Khasra No. (Ha.)	Area	Boundary
(1)	(2)	(3)	situated (4)	(5)	(6)	(7)
						•
1.	Kharora	Kharora	Raipur	4/1	0.275	North: Artificial line
		26	,	6/2, 3	0.672	Pillar No.1 to 14.
				6/1	0.340	
				7/1,2	1.352	East : Artificial line Pillar
				8/2	0.421	No. 14 to 23.
				13/1	0.890	
				13/3	0.121	South: Artificial line
				14/1, 2, 3	0.379	Pillar No. 23 to 49.
				17, 18, 19, 20	3.605	
		•		15, 16	0.583	West: Comp. No. 8 line
				12	1.100	New Pillar No. 49
				22	1.668	to 1.
				23	2.833	
				21/1, 2	1.368	

<u>(1)</u>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				•		
i.	Kharora	Kharora	Raipur	81/1	1.918	
		26		81/2	1.918	
				82, 83, 84, 83		
				. 86	0.429	
			•	87 88 ,	0.833 1.619	
			•	89/3	0.506	
				89/4	0.510	
				98	0.733	
				80	0.280	Under water
				79/1	0.379	
				79/2	0.194	
			•	78	0.591	
				77/1, 2	0.591	
				76/1, 2	1.769	
•				70	0.551	
		•		24/1, 2, 3, 4		
				25/1, 2 26/7, 6	1.668 6.021	
		•		11/3	0.021	
				27/1, 2	2.477	
	•			28/1	1.223	•
				31/5	0.113	•
	•			. 31/1	0.446	
				32/2	0.308	
				33/1, 2	1.214	
			,	30/2	0.663	
				99/1 Part	0.051	
				97 Part	0.187	
		•		31/3, 4	0.890	
			Total	. 44	47.505	
2.	Nahardih	Nahardih .	Kharora	1/1	0.461	North: Artificial line
		· 25		1/2	0.203	Pillar No. 1 to 9.
				1/3	0.202	
		•		1/4	0.320	East : Artificial line
		.'		1/5	0.231	Pillar No. 9 to 15.
				2 3	0.364 0.324	South: Artificial line
				4/1, 2	0.324	Pillar No. 15 to
				4/3, 4	0.158	19.
				5/1	0.162	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
				5/2	0.158	West: Artificial line
				6/1	0.121	Pillar No. 19 to 1.
				6/2	0.121	
				6/3	0.118	Note
	•			7/1	0.663	(A) Khasra Nos. 613. 614
				7/2	0.330	105 have been ring
				7/3	0.330	out by Pillar No. 1 to
				8	0.247	10.
	•			9/1	0.114	/D) I/I 51 142/-
•				9/2	0.344	(B) Khasra No. 115/2
				9/3	0.117	have been ring out
				9/4	0.113	by Pillar No. 1 to 4.
				10	0.567	•

进 · 声声

1	(0)	(2)	7.45			
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	. (7)
2.	Nahardih	Nahardih	Kharora	11	0.275	(C) Khasra Nos. 14/1
	1 (4/14/01)	25	· National	12	0.275	16/1, 16/3 have been
				13/1	0.101	ring out by Pillar No
				13/2	0.101	I to 7.
				13/3	0.105	1 10 7.
				13/4	0.162	
		•	•	13/5	0.263	
				13/6	0.202	.*
•				13/7	0.267	
	•			13/8	0.202	
				14/2	0.263	
			-	14/3	0.522	
				15/1	0.425	•
				- 15/2	0.271	
	•		_	15/3	0.271	
			•	16/2	0.555	
				17/1	0.457	
				17/2	0.457	
				18/1	0.405	
				18/3	0.809	
				18/4	0.404	
				19/1	0.394	•
				19/2	0.394	
				19/3	0.393	•
			•	21/4	0.599	
				21/2	1.793	
				23/2	0.534	•
	•			24/1	0.598	•
	•			24/2	1.845	•
			·	99/1	0.404	
		•		99/2	0.814	
				99/3	0.405	
				101/1	0.437	
				102/1	0.437	
				23/1	1.060	
				103/1	0.275	
				103/2	0.103	
		•		103/3	0.307	
				103/4	0.275	
	•	•		103/5	0.369	•
				104/1	0.595	
				21/3	0.599	•
				21/1	0.599	
				106/2	0.676	-
				107	0.344	
				108	0.724	
			-	109/1	0.375	•
			•	109/2	0.249	
				109/3	0.375	
				110	0.567	
				111	0.348	
				112	0.405	
		-		113/1	0.194	•
				113/2	0.194	

1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	Nahardih	Nahardih	Kharora	114	0.308	
		25		115/1	0.247	
			•	115/3	0.267	
				115/4	0.093	
				115/5	0,267	
				115/6	0.243	
		•		115/7	0.097	
		·		116	2.481	
			Total	85	34.361	
			Grand Total	129	81.866	

Brief Description

Said Land is of private ownership. Area has been transferred to Forest Department against the

area affected under Raipur Alloy and Steel Ltd.,

Reasons for Afforestation

Area is transferred to Fores Department to compensate loss of forest land due to iron ore

mining by Raipur Alloy and Steel Ltd., at Rajnandgaon District.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जयसिंह म्हस्के, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 9 जनवरी 2003

क्रमांक 216/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

·	•	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर∕ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वार: प्राधिकृत अधिकारी	ं का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	दनिया प. ह. नं. 15	4.78 -	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	नर्मदा व्यपवर्तन डुबान एवं नहर.

टीप : भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. के. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

अंबिकापुर, दिनांक 10 सितम्बर 2002

रा. प्र. क्र. 02/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उझेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

	Đ,	र्मि का वर्णन		धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	प्रतापपुर	प्रतापपुर	0.27	कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. संभाग क्र. 2, अंबिकापुर.	मुख्य सड्क प्रतापपुर से कालेज प्रतापपुर .तक पहुंच मार्ग का निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक कुमार देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ एवं उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/1/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	नारायणपाल	1.408	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, कोंडागांव.	नारायणपाल उद्वहन सिंचाई योजना की लघु नहर एवं उप- लघु नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ऋचा शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 3 जनवरी 2003

क्रमांक 127/प्र. 1/2002—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम. 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सृचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गर्ड शिक्तयों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

ंअनुसूची

	•	भूमि का वर्णन		धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	'('2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	केंवतरा प. ह. नं. 23	0.19	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	सुरही कर्रा व्यपवर्तन के मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 3 जनवरी 2003

क्रमांक 128/प्र. 1/2002—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनयम. 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

		भूमि का वर्णन		धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
জিলা	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4.)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	कोंगियाकला प. ह. नं. 20	0.14	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	सुरही कर्रा व्यपवर्तन नहर ढाप फीडर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आई. सी. पी. केसरी, कलेक्टर एवं पदेन अतिरिक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/755.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार मर्भा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के मंत्र के धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

		मि का वर्णन		· धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील .	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	बंजारी प. ह. नं. 8	2.178	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र.4 डभरा.	लिमगांव माइनर निर्माण हेतु.	

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/756. चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

	a di	मि का वर्णन		धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	· (4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	कलमी प. ह. नं. 5	1.648	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, ऋ.4 डभरा.	मालखरौदा माइनर निर्माण हेतु.

क्रमांक-क/भू-अर्जन/757.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- व्यर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दो जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

	a)	मि का वर्णन	•	ें धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर∕ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	पोता प. ह. नं. 6	0.668	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र.4 डभरा.	मुक्ता माइनर निर्माण हेतु.	

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/758.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

	Ý	र्मि का वर्णन		धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	पोता प. ह. नं. 6	0.802	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र.4 डभरा.	ं बीरभाठा माइनर निर्माण हेतु.

क्रमांक-क/भू-अर्जन/761.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

	9:	मि का वर्णन		धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर∕ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	ं के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौंदा	अड़भार प. ह. नं. 8	2.746	कार्यपालन यंत्री, मिनोमाता बांगो नहर संभाग, क्र.4 डभरा.	अडभार माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/762.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

	9	ूमि का वर्णन		धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर∕ग्राम	लगभग क्षेत्रफल · (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	अड़भार प. ह. नं. 8	12.040	कार्यपालन यंत्री, मिन्नीमाता बांगो नहर संभाग, क्र.4 डभरा.	हरदी उपवितरक निर्माण हेतु.

क्रमांक-क/भू-अर्जन/763.—चूंिक राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दो जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

	, મુ	मि का वर्णन		धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर∕ग्राम	लगभग क्षेत्रफल - (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन -
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	अंडी प. ह. नं. 6	0.548	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र.4 डभरा.	चरौदा माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-कं/भू-अर्जन/764.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम को धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची-

	भूरि	मे का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा '	कर्रापाली प. ह. नं. 9	0.593	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता वांगो नहर संभाग, क्र.4 डभरा.	टाटा माइनर निर्माण हेतु

क्रमांक-क/भू-अर्जन/765.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजिनक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एड़ने की संभावना/है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

	a.	मि का वर्णन		धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर∕ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	्र टाटा प. ह. नं. 9	1.514	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र.4 डभरा.	टाटा उपशाखा निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू–अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/766.—चूंकि राज्य शासन की यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

	ð.	ूमि का वर्णन		धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
<u> जिला</u>	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीरचांपा	मालखरौदा	जमगहन प. ह. नं. 6	1.425	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र.4 डभरा.	जमगहन सब माइनर निर्माण हेतु.

क्रमांक-क/भू-अर्जन/767.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

· .	9	गूमि का वर्णन		धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	् तहसील	नगर∕ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	बड़ेपाडरमुड़ा प. ह. नं. 6	3.299	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र.4 डभरा.	जमगहन सब माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांके 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/768. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

	a.	ूमि का वर्णन		धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
जांजगीर–चांपा	मालखरौदा	चिखली प. ह. नं. 11	1.082	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र.4 डभरा.	मालखरौदा माइनर निर्माण हेतु.	

क्रमांक-क/भू-अर्जन/769.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारो को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

	9	मि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला े	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	्का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	`(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	खरताल प. ह. नं. 9	0.253	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र.4 डभरा.	खरताल माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है:

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/770.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
<u> </u>	तहसील	नगर∕ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	ंका वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	बीरभाठा प. ह. नं. 5	1.356	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता वांगो नहर संभाग, क्र.4 डभरा.	बीरभाठा माइनर निर्माण हेतु.

.क्रमांक-क/भू-अर्जन/771.—चूंिक राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दो जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

	યૃ	मि का वर्णन		धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर∕ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
.(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालंखरौदा	मुक्ताठाकुर प. ह. नं. 5	5.186	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र.4 डभरा.	मुक्ता माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्सा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/772.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

	97	्मि का वर्णन		धारा ४ की उपधारा (2)	सावजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर∕ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	किरकार प. हं. नं. 11	0.417	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र.4 डभरा.	किरकार माइनर निर्माण हेतु. ,

क्रमांक-क/भू-अर्जन/773.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

	9	्मि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
<u>जिला</u>	तहसील.	नगर/ग्रा म -	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	झर्रा प. ह. नं. 9	1.512	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बागो नहर संभाग, क्र.4 डभरा.	झर्रा माइनर (सिंधरा फगुरम) निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/774.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजिनक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

	3	र्मि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर∕ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चां पा	मालखरौदा	झर्रा प. ह. नं. 9	0.150	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र.4 डभरा.	सपिया माइनर निर्माण हेतु.

क्रमांक-क/भू-अर्जन/775.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

	_ ^
ಾಸವ	प्रज्ञा
ञान	त्र पा
	, ~

भूमि का वर्णन				धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	झर्रा प. ह. नं. 9	2.065	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र.4 डभरा.	फगुरम सब डि. ब्यू. निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/776.—चूंिक राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

,	27	मि का वर्णन		धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	तौलीपाली प. ह. नं. 9	2.508	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र.4 डभरा.	फगुरम डि. ब्यू. निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार. मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

्रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/30/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में विर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपवंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संवंधित व्यक्तियां को इस आशय को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

	Ŋ	ूमि का वर्णन	•	धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जিলা	तहसील	नगर∕ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	की वर्णन -
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	रामपुर	2.714	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	लोवर भण्डोरा जलाशय के रामपुर माइनर निर्माण कार्य हेतु.

रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/30/अ-82/2002-2003—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में विर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उस्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

	9	र्गुमि का वर्णन		धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	· का वर्णन
(1) _,	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	गदहाभाठा प. ह. नं. 14	0.839	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	जोंक शाख्जै नहर क्रमांक 25 के निर्माण कार्य हेतु.

क्रमांक क/भू-अर्जन/31/अ-82/2002-2003—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

	8	र्मि का वर्णन		धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
জিলা	तहसील	नगर∕ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन ं ं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	जोरा प. ह. नं. 14	2.218	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	जोंक टेल शाखा नाली निर्माण कार्य हेतु.

रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/32/अ-82/2002-2003—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजिनक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

	9	भूमि का वर्णन		धारां 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	गिरवानी प. ह. नं. 13	1.655	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन े निर्माण संभाग, कसडोल.	जोंक शाखा नहर क्रमांक 21 का उप-शाखा नहर निर्माण.

क्रमांक क/भू-अर्जन/33/अ-82/2002-2003—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उझेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

	9	भूमि का वर्णन	·	धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
<u>জিলা</u>	तहसील	नगर∕ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	. का वर्णन
(1)	. (2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	विलाईगढ़	चिकनीडीह प. ह. नं. 14	1.649	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	जोंक शाखा नहर क्र. 25 के निर्माण कार्य हेतु.

रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/34/अ-82/2002-2003—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजिनक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

	3	मि का वर्णन	•	भारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर∕ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1).	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
. रायपुर	बिलाईगढ़	वोटगन प. ह. नं. 14	2.223	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	जोंक अंतिम शाखा नहर निर्माण कार्य हेंसु.

क्रमांक क/भू-अर्जन/35/अ-82/2002-2003—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उस्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

	٩	भूमि का वर्णन		धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर∕ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का व र्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	सलौनीकला प. ह. नं. 13	0.515	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	जोंक शाखा नहर क्रमांक 25 के निर्माण कार्य हेतु.

रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2002

क्रमांक क/मू-अर्जन/36/अ-82/2002-2003—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपेधारा (1) के उपवंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

	2	ूमि का वर्णन		धारा ४ की उपधारा (2)	'सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर∕ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	नवापारा प. ह. नं. 17	2.891	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	जोंक खपरीडीह शाखा नहर निर्माण कार्य हेतु.

क्रमांक क/भू-अर्जन/37/अ-82/2002-2003—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजिनक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

	9	र्मि का वर्णन		धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर∕ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	. (4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईंगढ़	जुनवानी प. ह. नं. 17	0.831	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	जोंक खपरीडीह शाखा नहर निर्माण कार्य हेतु.

रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/38/अ-82/2002-2003—चूंिक राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में विर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजिनक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उछिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

	. 9	मि का वर्णन		धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नग√ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	वोटगन प. ह. नं. 14	1.134	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	जोंक शाखा नहर क्र. 26 के निर्माण कार्य हेतु.

क्रमांक क/भू-अर्जन/39/अ-82/2002-2003—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उक्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

	9	मूमि का वर्णन		धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर∕ग्राम .	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा [.] प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	· (6)
रायपुर	बिलाईगढ़	जुनवानी प. ह. नं. 17	2.903	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल	जोंक अंतिम शाखा नहर निर्माण कार्य हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमिताभ जैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

राजस्व विभाग कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/01/अ-82/89-90.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

J.	7	П	771
71	- 1	S	'41
	~	Ç	`

- (1) भूमि का वर्णन-
 - (क) जिला-बस्तर
 - (ख) तहसील-जगदलपुर
 - (ग) नगर/ग्राम-सालेमेटा, प.ह.नं. 36
 - (घ) लगभग क्षेत्रफल-12.467 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकवा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
138	2.286
139	3.780
141/1	0.251
. 142	1.295
134/1	0.526
143	3.318
134/1	0.567
134/1	0.202
134/1	0.242
योग	12.467

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोसारटेडा परियोजना की स्पोल चैनल निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एल. एन. सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सन्चिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 7 दिसम्बर 2002

संशोधन

क्रमांक 17196/भ्-अर्जन/2002. — भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 4/अ-82/2001-2002/15386 दिनांक 23-10-2002 ग्राम झांझ एवं भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 8/अ-82/2001-2002/15384 दिनांक 23-10-2002 ग्राम नेवसा की अधिसूचना के अनुसूची में आंशिक तुटि प्रकाशित हुआ है, जिसमें संशोधन की आवश्यकता है. जो निम्नानुसार है:—

दिनांक 15-11-2002 को राजपत्र में प्रकाशित

ग्राम	खसरा नम्बर	रकवा (हेक्टेयर में)
झांझ नेवसा	252/1 1/1 थ	0.024 0.142
٠	वर्तमान में संशो	धित
ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
झांझ नेवसा	352/1 1/1 ਰ	0.024 0.142

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, **ईशिता रॉय,** कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

